



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05042023-244933  
CG-DL-E-05042023-244933

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1543]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 5, 2023/चैत्र 15, 1945

No. 1543]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 5, 2023/CHAITRA 15, 1945

## दिल्ली विकास प्राधिकरण

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2023

एम्स की मुख्य योजना के कार्यान्वयन के लिए भू-खण्डों के समामेलन के उद्देश्य हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फैक्टरी रोड पर एम्स ट्रामा सेंटर के पास 219 वर्ग मीटर भूमि का केंद्र सरकार (एल एण्ड डी ओ) को अंतरण।

**का.आ.1621(अ).**—एम्स, नई दिल्ली की मुख्य योजना के कार्यान्वयन के लिए भू-खण्डों के समामेलन के उद्देश्य हेतु दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 22(4) के अंतर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण एतद्वारा केंद्र सरकार (एलएण्डडीओ) को 219 वर्गमीटर भू-खण्ड अंतरित करता है। इस भूमि को प्राधिकरण संकल्प संख्या 114 दिनांक 06.05.1961 में विनिर्दिष्ट निबंधन एवं शर्तों पर दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 22(1) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा डीडीए के निपटान हेतु रखा गया था।

उक्त भूमि का अंतरण निम्नलिखित निबंधन एवं शर्तों के अधीन होगा:-

- भूमि के सभी आबंटन, चाहे नीलामी द्वारा हों या अन्य किसी प्रकार से हों, केवल लीज होल्ड आधार पर ही होंगे।
- नीलामी अथवा पूर्व निर्धारित दरों पर आबंटन के मामले में भू-भाटक (ग्राउण्ड रेंट) पहले पाँच वर्षों के लिए प्रति प्लॉट नाममात्र 1 रुपया प्रति वर्ष लिया जाएगा। इसके बाद वार्षिक भू-भाटक वास्तविक रूप से भुगतान किए जाने वाले प्रीमियम के 2.5% पर देय होगा। भू-भाटक की दर प्रत्येक 30 वर्ष के बाद संशोधन के अधीन होगी।
- लीज डीड सरलीकृत होगी तथा इसमें निम्नलिखित शर्तें शामिल होंगी:-
  - नगरपालिका संबंधी उप-विधि का उचित अनुपालन ;
  - भूमि का वैसा ही उपयोग जिसके लिए वह आबंटित की गई है ;
  - निर्धारित समय में निर्माण;
  - भूमि के किसी भी हित को अंतरित करने से पहले अनुमति लेना ;

- ड. भूमि के अंतरण पर पचास प्रतिशत अनर्जित वृद्धि को सरकार के साथ साझा करना;
- च. नियमित रूप से भू-भाटक भुगतान करने की बाध्यता;
- छ. उपर्युक्त शर्तों में से किसी एक को भी पूरा न करने की स्थिति में पुनः जाँच (री-एंट्री) करना अथवा आंशिक अथवा पूर्ण प्रीमियम को जब्त करना।
- iv. निम्नलिखित अर्थात्-
  - क. स्कूल, अस्पताल, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा अन्य धर्मार्थ संस्थाएँ;
  - ख. धार्मिक, राजनीतिक अथवा अर्ध-राजनीतिक संगठन, और
  - ग. लाभप्रद, अर्ध-लाभप्रद और अलाभप्रद उद्देश्यों हेतु स्थानीय निकायों को भूमि का आबंटन, प्राशुल्क दर और प्राप्य भू-भाटक भारत सरकार के विद्यमान आदेशों द्वारा शासित किया जाना जारी रहेगा।

[फा. सं. एफ. 22(5)/06/आईएल]

डी. सरकार, आयुक्त एवं सचिव

### DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2023

**Transfer of 219 sqm. of land along AIIMS Trauma Centre on Factory Road by Delhi Development Authority (DDA) to Central Government (L&DO) for the purpose of amalgamation of land parcels for implementation of Master Plan of AIIMS.**

**S.O. 1621(E).**—Delhi Development Authority hereby transfers a land parcel measuring 219 sqm to Central Government (L&DO) under Section 22(4) of the Delhi Development Act, 1957 for the purpose of amalgamation of land parcels for implementation of the Master Plan of AIIMS, New Delhi. The land was placed at the disposal of DDA by Central Government under section 22(1) of Delhi Development Act, 1957 on terms and conditions specified in Authority Resolution no. 114 dated 06.05.1961.

The transfer of said land will be subject to the following terms and conditions: -

- i. All allotments of land whether by auction or otherwise, shall be only on leasehold basis.
- ii. Ground rent will be charged at a nominal rate of Re.1/- per annum per plot for the first five years in the case of allotments whether by auction or at pre-determined rates. Thereafter, the annual ground rent shall be payable at 2.5% of the premium originally paid. The rate of ground rent will be subject to revision after every 30 years.
- iii. Lease deeds will be simplified and will contain in the following conditions: -
  - a. Due observance of municipal bye-laws;
  - b. Use of the land for the purpose for which it is allotted;
  - c. Construction within the stipulated time;
  - d. Requiring permission before transferring any interest in the land;
  - e. Sharing with the Government, fifty percent of unearned increase on transfer of the land;
  - f. Obligation to pay ground rent regularly;
  - g. Re-entry and forfeiture of premium in part or in full if any of the above conditions is not fulfilled.
- iv. The allotment of land to and the rates of premia and ground rent recoverable from –
  - a. schools, hospitals, social, cultural and other charitable institutions;
  - b. religious, political or semi-political organization; and
  - c. local bodies for remunerative, semi remunerative and un-remunerative purposes will continue to be governed by the existing orders of the Government of India.

[F. No. F. 22(5)/06/IL]

D. SARKAR, Commissioner-Cum-Secy.